सलाम करते हैं इसी तरह से ठेले वाला, कार वाला जो अपने आप को मालिक समझता है सारी सड़क का जब कि मालिक उस का किसान है और वह सड़क उस की है उस को सड़क पर नहीं चलने देना चाहते तो उस की कम से कम इतनी इज्जत तो कर दें, वह चाहे मिनिस्टर हों, चव्हाण साहब हों, उन की कार हो तो वह ऐसा निशान करें कि जिस में मालूम पड़े कि मेरा सलाम कबूल करे किसान। किसान तो इसी बात पर खुश हो जायगा।

16.00 hrs.

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि जहां बड़े-बड़े शहर हैं वहां तो राव साहब ने रिंग रोड नेशनल हाइ-वे या बड़े-बड़े हाइ-वे पर दे दी है, लेकिन गांववालों ने क्या जुल्म किया है, गांव के बीच में से नेशनल हाइ-वे या बड़ी हाई-वे गुजरती है, उस में बाइ-पास नहीं दिया है। हमारे गांवों की बच्चियां, गरीब हरिजनों, गरीब मजदूरों, गरीब किसानों के बच्चों की रोज़ाना मौतें होती हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि ये ट्रक वाले कितनी लापरवाही से ट्रक चलाते हैं......

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may resume his speech on the next occasion.

— —

16.01 hrs.

DISCUSSION RE : CENTRE STATE RELATIONS

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की समस्या बहुत गम्भीर है और यह समस्या पिछले दो सालों से तो और भी ज्यादा जटिल हो गई है, टेढ़ी और पेचीदा हो गई है। जब 1967 में आम चुनावों के बाद देश में क्रान्ति आई तो अमृतसर से लेकर अगर गाड़ी कलकत्ते तक चली जाय, बल्कि भुवनेश्वर तक जाय, तो जहां पर पहले कांग्रेस की राजसत्ता थी, वहां पर गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं।... ...(व्यवधान)...

अब प्रश्न यह है कि ये पेचीदगियां क्यों आईं? इस के दो कारण हैं दो साल पहले, उपाध्यक्ष जी, भारत में केन्द्र तथा राज्यों में प्रायः कांग्रेस की सरकारें थीं, इस लिये कभी-कभी थोड़ा-बहुत मतभेद होता था, लेकिन कोई जटिल समस्या नहीं बनी और इस का दूसरा कारण यह था कि देश में पं० जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्ति की टावरिंग-परसनेलिटी थी, जिनका सब सम्मान करते थे। लेकिन ये दोनों बातें 1967 के बाद नहीं रहीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि समस्या दिन पर दिन बढ़ती गई।

अगर पिछले दो साल की कहानी को आप देखें तो आप पायेंगे कि यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों की कहानी बड़ी दर्दनाक और कम्पलीकेटेड रही है। किस ढंग से केन्द्र ने राज्य सरकारों से बर्ताव किया, अगर यह चीज देखी जाय तो इस के भयानक नतीजे निकलेंगे। अपनी पार्टी के लिये राजनीति को लाकर किस तरीके से इन लोगों ने गैर-कांग्रेसी सरकारों को, जो आधे से ज्यादा देश में बनाई गई थीं, उल्टा, सिस्टेमेटिक तरीके से उल्टा, लोगों के वर्डिक्ट को पलटने की साजिश की गई, उस की मिसाल नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि हमारे देश का कांस्टीचूशन फैडरल है, जैसा फैडरल कांस्टीचूशन हमारे देश में है वैसा दुनिया के और किसी देश में नहीं है। केन्द्र और राज्यों के जो अधिकार इस पार्लियामेन्ट ने बनाये हैं, उन का पालन हर राज्य सरकार को करना चाहिये। हमारे केन्द्र को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य सरकार को डायरेक्टिव दे सकती है, उनकी बाउन्ड्री को भी चेन्ज कर सकती है, एडजस्टमेन्ट भी कर सकती है, यहां तक कि राज्य सरकारों को खत्म भी कर सकती है। ये सब पावर्ज़ दुनियां के किसी और फैडरल कांस्टीचूशन में नहीं हैं। मैं डा० अम्बेदकर को भी इस अवसर पर कोट करना चाहता हूं—वह कांस्टीचूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था—

[श्री कंवर लाल गुप्त]

"The Committee wanted to make it clear that though India was a federation, the federation was not the result of an agreement by the States to join a federation.. and no State has the right to secede from it. The country is one integral whole, its people a single people living under a single imperium derived from a single source."

उपाध्यक्ष महोदय, यह देश एक है और हमारे दल की यह मान्यता है कि इस में यूनीटरी टाइप की गवर्नमेन्ट होनी चाहिये, एक सरकार होनी चाहिये, लेकिन जब फैडरल गवर्नमेंट है, दोनों चीजें बंटी हुई हैं, अधिकार बंटे हुए हैं, तो केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि दोनों में बैलैंस रखा जाय, राज्य सरकारों को खुली छूट देनी चाहिये कि वे अपने इनिशियेटिव से जितना काम कर सकें, करें, लेकिन देश के अहित में नहीं, जो केन्द्र को चेलेंज कर के नहीं करना चाहिये। एक ऐसा बैलेंस्ड कोड बनाना चाहिये था, जिससे कि दोनों के सम्बन्ध अच्छी प्रकार से चलते, लेकिन, उपाध्यक्ष जी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार इस में बुरी तरह से नाकामयाब रही है। उन को जिस तरह का आदर्श केन्द्र सरकार के नाते रखना चाहिये था, उस तरह का आदर्श नहीं रखा।

पहला तीर जो चव्हाण साहब के तरकस से निकला—वह राजस्थान था। वहां की असेम्बली को भंग करने के बारे में निकला। वहां पर कांग्रेस की मैजोरिटी नहीं थी, लेकिन किसी भी बहाने से इन्होंने गवर्नर को कहा और गवर्नर ने थोड़े दिन के लिये असेम्बली को भंग कर दिया, इस बीच में वहां हाउस-ट्रेडिंग होती रही और आखिर में जब कांग्रेस की मैजोरिटी बन गई, उस के बाद उस असेम्बली को फिर जिन्दा कर दिया गया। इतना ही नहीं उस के बाद बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, इन्होंने माइनौरिटी गवर्नमेन्ट्स बनाईं—जहां पर कि गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं। उपाध्यक्ष जी, मिनि-स्कर्ट और मिनि-शर्ट तो नौजवान लड़के-लड़कियां पसन्द करते हैं, लेकिन जब एक बूढ़ा आदमी और वह भी गृह-मंत्री हो, वह मिनि-गवर्नमेन्ट पसन्द करे—लड़के-लड़कियों का मिनि-शर्ट या मिनि-स्कर्ट पहनने से यह होता है कि कुछ हिस्सा नंगा रहता है, लेकिन इन्होंने तो मिनि-सरकारें पैदा कर के.....

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गुप्ता जी, ये मिनि-डिक्टेटर्स हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मिनि-सरकारें पैदा कर के गृह मंत्री स्वयं तो नंगे हो ही गये, लेकिन दुनियां के सामने सारे भारत की डेमोक्रेसी को भी नंगा कर दिया।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। वकील हो कर भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री कंवर लाल गुप्त : जिस तरह से इन्होंने बिहार में किया—मंडल को चीफ़ मिनिस्टर बनाने के लिये पहले एक आदमी को तीन दिन के लिये चीफ मिनिस्टर बनाया, उस के बाद उन को नौमिनेट कराया—हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह की कहानियां चलती गईं—इसी तरह से पंजाब में हुआ, मैं उस लम्बे किस्से में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक प्रकार से नान-कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिये कांस्पिरेसी की गई—इस काम के लिये गवर्नर की इंस्टीचूशन को यूटिलाइज किया गया, मिस-यूज किया गया—पार्टी-एण्ड्स के लिये—यह डेमोक्रेसी पर एक जबरदस्त चोट थी।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नर जो लोग बनाये गये—किन को बनाया गया—जो सैकेण्ड-रेट के लोग थे, जो इलैक्शन में हार गये थे, उन लोगों को गवर्नर बनाया गया, ताकि वे इन के हाथों में कठपुतली की तरह से नाचें, कांस्टीचूशन के मुताबिक काम न कर

पायें, गवर्नर की जो ताकत है, गवर्नर के लिये जो कायदे-कानून हैं, उन को भुलाकर उन्होंने यह सब कुछ किया। मैं यह भी जरूर मानता हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया, वह तो निंदनीय है ही, लेकिन हमारी तरफ़ से भी बंगाल के स्पीकर ने पंजाब के स्पीकर ने जो कुछ किया, उस को डिफेण्ड नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं कि अगर देश में प्रजातन्त्र को रखना है तो विरोधी पक्ष को भी उतना ही जिम्मेदार होना पड़ेगा जितना कि हम सरकार से मांग करते हैं, तभी दोनों बैलंस्ड हो कर ठीक ढंग से काम चला सकते हैं।

मेरी मांग यह है कि जिस तरह से गवर्नर की इंस्टीचूशन को इन्होंने मिसयूज़ किया है कोई ऐसा तरीका बनाया जाना चाहिये जिससे कि गवर्नर की नियुक्ति आइन्दा इण्डिपेन्डेन्ट लोगों में से हो जो संविधान के मुताबिक चलें। ऐसा न हो कि कोई मंत्री हार जाय, तो उस को गवर्नर बना दिया जाय, यह मिनिस्ट्री आफ़ रिहैबिलीटेशन नहीं होना चाहिये।

दूसरी चीज़ जो दो साल के तजुर्बे से हम ने सीखा है, वह यह है कि हमारे विधान में गवर्नर को इम्पीच करने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर को इम्पीच करने का कोई अधिकार हमारे विधान में नहीं है। इस लिये मैं मांग करना चाहता हूँ कि गवर्नर को भी इम्पीच करने की ताकत विधान में होनी चाहिये, क्योंकि राष्ट्रपति उन को नियुक्त करता है, इस लिये हो सकता है कि राष्ट्रपति की मर्जी के बगैर भी गवर्नर कभी कोई गलत बात कर दें इसलिए गवर्नर को किस तरह से इम्पीच किया जाए, यह चीज भी विधान में होनी चाहिये। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि रांची में कुछ राय्टस हुए थे, वहां के उस समय के चीफ मिनिस्टर, महामाया बाबू ने कहा कि मैं कमेटी नियुक्त करता हूँ, जुडिशल इंक्वायरी कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या कारण हैं लेकिन उनको बगैर पूछे केन्द्र ने अपनी तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। जब राज्य सरकार उसके लिए तैयार थी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके लिए एक अलग कमेटी बिठाने की क्या जरूरत थी? जब वे कमेटी बिठा ही रहे थे तो फिर उनके साथ सहयोग करना चाहिए था।

इतना ही नहीं, जहां तक फाइनेंशल मैटर्स का सम्बन्ध है, स्टेट्स के एलोकेशन्स बहुत कम हैं। पैसे की वजह से स्टेट्स में एक फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है।...(व्यवधान)...मेरा कहना यह है कि आज कल क्या हो रहा है? 40 परसेंट से लेकर 80 परसेन्ट तक स्टेट्स को एलोकेशन होना है केन्द्र की ओर से लेकिन 40 परसेन्ट और 80 परसेन्ट में भेदभाव क्यों होता है? किसी को 40 परसेन्ट दिया जाता है और किसी को 80 परसेन्ट दिया जाता है और यह केवल एक आदमी के व्हिम के ऊपर ही निर्भर करता है। आप कहते हैं कि अगर आपको बोलना है तो स्पीकर की आई कैच कीजिए और फिर हमको मौका मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या है? अगर पैसा लेना है — We will not get anything unless we catch the feet of the Finance Minister. This is the position. हरएक स्टेट को एक म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दे दिया गया है जिसके कारण उनमें फ्रस्ट्रेशन है। मैं चाहता हूँ कि उनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, ज्यादा पैसे का एलोकेशन होना चाहिए और प्रायर्टीज फिक्स होनी चाहिए। एक परमानेन्ट फाइनेन्स कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए जोकि इन चीजों को तय करे। आपने एक सोकाल्ड एन० डी० सी० बना रखी है, नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल जिसका कोई जवाब नहीं है। खुद मैसूर के चीफ मिनिस्टर, श्री वीरेन्द्र पाटिल ने 28-8-68 को यह मांग कर रखी है कि एक परमानेन्ट फाइनेंस कमीशन सेटअप होना चाहिए जोकि पावर्स और लेयर आफ मनी को डिफाइन करे। आर्टिकल 275 में, कितनी ग्रान्ट्स मिलनी चाहिएं, यह चीज बताई गई है।

अब मैं केरल की ओर आता हूँ जोकि वास्तव में क्रक्स आफ दि प्राब्लम है। वहां पर

[श्री कंवर लाल गुप्त]

पहला सवाल यह है कि सी० आर० पी० को केन्द्र ने भेजा। क्या सी० आर० पी० को भेजने का अधिकार केन्द्र का था ? मैं मानता हूँ कि सी० आर० पी० को भेजने का अधिकार केन्द्र को था। यह चीज़ हरएक ने मानी है। स्वयं केरल के चीफ मिनिस्टर, श्री नम्बूद्रीपाद ने भी कहा है कि केन्द्र को अधिकार था। लेकिन मैं ने पहले भी यह सवाल किया था कि अधिकार था अधिकार है लेकिन आपको राज्य सरकार से पूछना चाहिए था। आपने क्यों नहीं पूछा, इसका जवाब चव्हाण साहब नहीं देते हैं। गोलमोल आफिशल्स के नाम पर बोलने वाले सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि पूछने का क्या फायदा था, हमें तो उनके विचार पहले से ही मालूम थे। आपको यह मालूम था कि यह जो केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल है इसके बारे में राज्य सरकारों में मतभेद है, इसके बारे में पार्टियों में मतभेद है तब तो आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी था कि आप उनसे सलाह करते। और सलाह करने के बाद फिर आपको पूरा हक था कि जो चाहें करें...(व्यवधान)...

SHRI NAMBIAR (Tiruchirapalli) : He said, there was no necessity to consult.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मानता हूँ कि यह विधान में राइट है और विधान में राइट होते हुए यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ़ न भी हो लेकिन इसमें कांस्टीट्यूशन की इम्प्रो-प्रायटी जरूर है। आखिर आप किस ढंग से देश को चलाना चाहते हैं ? क्या एक हाथ में कांस्टीट्यूशन की किताब लेकर और दूसरे हाथ में डंडा लेकर आप राज्य सरकारों से कहेंगे कि यह विधान है, या तो इसको मानो या फिर तुम्हारे सिर पर डंडा पड़ेगा। इस प्रकार से तो कोई भी केन्द्रीय सरकार राज्यों के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकती हैं और अगर ऐसी गलतफहमी में कोई हो तो उसे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, इस प्रकार से कभी होने वाला नहीं है। तो इसमें कांस्टीट्यूशन की इम्प्रोप्रायटी की बात है जोकि इस सरकार ने नहीं की।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जब बिहार में गवर्नर के एप्वाइन्टमेन्ट का सवाल आया तो आपने चीफ मिनिस्टर से पूछा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें यह गवर्नर नहीं चाहिये लेकिन उसके बाद भी आपने वही गवर्नर भेजा। ठीक है। बिहार गवर्नमेन्ट को मना करना चाहिए था या नहीं मना करना चाहिए था, वह अलग बात है लेकिन जैसी कि आपकी परम्परा रही है, आपने उनसे पूछा उसी तरह से आपको सी० आर० पी० के बारे में भी सलाह करनी चाहिए थी।

सी० आर० पी० का आरम्भ में जो निर्माण हुआ था वह पुलिस फोर्स की तरह से नहीं हुआ था जिस ढंग से कि आप अब चल रहे हैं, सी० आर० पी० को प्रिलिमिनरी फोर्स बना रहे हैं, राज्य सरकारों की पुलिस के साथ-साथ। सन् 1948 में जबकि सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उस समय जो एक बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, उस समय के उनके भाषण से मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा। यह सी० आर० पी० जो बनी थी यह पहले क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस लाइन पर बनाई गई थी। राज्य सरकारों और राजा-महाराजाओं की जो रियासत थीं उनको सहायता देने के लिए जो पुलिस हुआ करती थी वह उनके नीचे हुआ करती थी इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि चूंकि उनके पास अधिक फोर्स (पुलिस) नहीं है और उनको सहायता की जरूरत पड़ती है इसलिए सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का निर्माण किया गया। आपकी आज्ञा से मैं उसमें से कोट करना चाहता हूँ :

> "We have told the Provinces that they should as far as possible be self-sufficient in their requirements for internal security. The Police forces for the Unions and States are in the process of formation. We shall still require considerable time before they function anything like the manner in which Provincial police forces have been functioning. We must, therefore, have a force for the interim period (mark the words *interim period*) and having regard to the State in which the

police forces of the Unions and States are at present, I am afraid that the interim period is going to be a pretty long one. Thirdly, a process of re-organisation of State forces is also on and during this process of reorganisation, it will be most useful to have a force which would take the first shock of any threat to security."

16.10 hrs.

[Mr. Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि इसके पीछे जो बैकग्राउन्ड थी वह यह थी कि अगर कहीं राज्य सरकारों की जरूरत पड़ती है जैसे कि उड़ीसा सरकार को पड़ी तो उस के मतलब के लिए यह बनाई गई थी। लेकिन आपने इसको एक प्रिलिमिनरी फोर्स बनाकर खड़ा कर दिया है। ...(व्यवधान)...

अब एक चीज और चल रही है कि जो सी० आर० पी० है जोकि अभी प्राजीक्यूशन नहीं कर सकती है या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, उस के लिए सी० आर० पी० के ऐक्ट में परिवर्तन किया जाए ताकि उसको प्राजीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की पावर भी दी जा सके। अगर सरकार ने ऐसा बिल सदन में रखा और सदन से पास भी करा लिया तो फिर उससे केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधों में खलबली मच जायेगी, एक हाहाकार मच जायेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने केरल से हैंडलिंग की है यह ठीक नहीं की है। मैं जानता हूँ कि आपने केरल सरकार से कहा कि जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उसको पूरी तरह से अमल में लाना चाहिए, पहले केरल के चीफ मिनिस्टर ने नहीं माना लेकिन जब आपने लेटर लिखा तो उन्होंने मान लिया लेकिन फिर भी एक चीज उन्होंने नहीं मानी। आपने कहा कि जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उनको पहले गिरफ्तार करो, इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को देने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना। आपने दोबारा भी चिट्ठी लिखी लेकिन उसके बाद भी वे नहीं माने। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया ? आप कम्युनिकेशन करते हैं और उसका जो तरीका आपने अपनाया उस पर मुझे एतराज है। आपने अपनी सी० आर० पी० भेज दी, ठीक है लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप यह महसूस करते हैं कि उन्होंने वायलेशन किया है, स्वयं नम्बूद्रीपाद जी ने कहा है कि हमने कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट का वायलेशन किया है, और अगर आप यह समझते हैं कि उन्होंने स्पिरिट या लेटर का वायलेशन किया है तो आप ने डायरेक्टिव क्यों नहीं भेजा ?

यह देश आपसे मांग करता है कि जो राज्य सरकार केन्द्र की अवहेलना करती है और उसे चेलेंज करती है उसे केन्द्र को उसका योग्य स्थान अवश्य बतला देनी चाहिए।

कुछ भाई यह कहते हैं कि सी० पी० आई० एम० को बेन करना चाहिये सी० पी० आई० (राइट) को बैन नहीं करना चाहिये या नक्सेलाइट्स को बैन कर देना चाहिये तो मेरी निगाह में इन तीनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। सांप, सांप ही हैं, चाहे वह कैसा भी हो। इसलिए मैं इन तीनों में किसी में भेद नहीं समझता हूँ। तीनों ही ग्रुप्स की लाएल्टी संदिग्ध है, तीनों की ही लाएल्टी बाहर है और यह तीनों ही पार्टियां पार्लियामेंटरी सिस्टम में विश्वास नहीं करती हैं। अलबत्ता अगर फर्क है तो सिर्फ स्ट्रेटिजी में है बाकी उनमें और कोई फर्क मेरी नजर में नहीं है। यह बिलकुल साफ बात है कि तीनों ही पार्लियामेंटरी सिस्टम में विश्वास नहीं करती हैं.....

SHRI NAMBIAR : With due respect to the hon. Member, if there is any reference to CPI(M), I stand here to refute it with all the emphasis at my command.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, with your permission, I want to quote a Kerala Minister, Shrimati Gauri :

> "Her party was in office, not out of any faith in parliamentary system of government, but because it wanted to use the administration as a tool for agitation."

[श्री कंवर लाल गुप्त]

अध्यक्ष महोदय, यह उन्होंने एलिपी में कहा है और वह सब अखबारों में छपा है। अब मेरा कहना यह है कि जब आप यह समझते हैं कि ये लोग पार्लियामेंटरी सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं तो आपने क्यों नहीं उनको डाइरैक्टिव दिया ? हमारा जो कांस्टीट्यूशन है वह अमरीका के तर्ज का नहीं है। अमरीका में क्या है अमरीका में जब वहां पर रेसियल राएट्स हुए और कैनेडी ने केन्द्र से पुलिस भेजी थी लेकिन उनको वह डाइरैक्टिव नहीं दे सकते थे। लेकिन आप को यहां डाइरैक्टिव देने का अधिकार है तो आपको डाइरैक्टिव देना चाहिए और इस तरीके से अमल नहीं करना चाहिये जैसा कि आपने वहां के लिए किया। अगर आप यह समझते हैं कि कम्युनिस्टों ने कोई गड़बड़ की है तो हम आप से मांग करते हैं कि कोई आप को व्हाइट पेपर निकालना चाहिये कि फलां-फलां लोग वाएलैंस में बिलीव करते हैं, या कौन-कौन लोग अथवा ग्रुप्स हैं जिन्होंने कि वहां पर वाएलैंस की है और किन-किन चीजों में आपकी बात नहीं मानी है। साथ ही मैं यह भी मांग करता हूँ कि जो आपकी और उनकी करसपौंडेंस है वह भी लोगों के सामने आनी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि आप ठीक हैं या वह ठीक हैं.....

SHRI NAMBIAR : We welcome the white paper. Let us have a discussion on it.

श्री कंवर लाल गुप्त : दूसरी चीज देखने की यह है कि इस केन्द्रीय सरकार का नौन-कांग्रेस गवर्नमेंट्स के लिए क्या रवैय्या रहा है। वर्तमान प्रधान मंत्री महोदया ने प्रधान मंत्री बनने के बाद यह चीज कही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमें इस ढंग से काम चलाना है जिससे कि केन्द्र और गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के आपसी सम्बन्ध ठीक तरीके से चलें लेकिन मुझे खेद के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि वह केवल उनके कहने की बात थी और कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। मुझे कहने दिया जाय कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार ने डबल स्टैन्डर्ड का परिचय दिया है। इन का यह डबल स्टैन्डर्ड हम लोग यहीं दिल्ली में भुगते हुए हैं। वक्फ बोर्ड एक छोटा सा मामला जो कि ट्रांसफर्ड सब्जैक्ट है उस वक्फ बोर्ड के कम्पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक का हर एक आदमी इंटरेस्टेड था और वह अपने अपने आदमी उस में नौमिनेट करने के लिए किस तरीके से किया वह सब चीजें आपके सामने हैं। इतना ही नहीं एक बोर्ड आफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का बनना है। अब एजुकेशन यह एक ट्रांसफर्ड सब्जैक्ट है लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जो उधर बैठे हैं उसे हमें नहीं बनाने देंगे। इतना ही नहीं लोकल सैल्फ गवर्नमेंट एक ट्रांसफर्ड सब्जैक्ट है और उपराज्यपाल महोदय ने साल में दो, तीन बार गृह मंत्री महोदय को लिखा कि कारपोरेशन को तोड़ देना चाहिये। यह लिखा है या लिखवाया जाता है वह एक सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस ढंग से आप राज्यों के साथ अपने सम्बन्ध रक्खेंगे और क्या यह तरीका अपनायेंगे ? जाहिर है कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह दो साल में क्या कुछ हुआ और कौन सी गलती राज्य सरकारों की है और कौन सी गलती केन्द्र की है इस का एक असैसमेंट होना चाहिए। या तो कोई पार्लियामेंटरी कमेटी बनायें या कोई एक इंडिपेंडेंट कमेटी अथवा कमिशन होनी चाहिए जो कि इस की जांच करे कि किस तरीके से प्रान्तों में स्थापित गैर कांग्रेसी सरकारें गिराई गई हैं किस तरीके से उन्हें समाप्त किया गया है। जब मैं यह कहता हूँ तो कोई पोस्टमार्टम के हक में मैं नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि आइन्दा के लिए वह एक गाइडिंग लाइन हो जायगी।

एक मेरा निवेदन यह है कि आर्टिकिल 263 का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है :

"If at any time it appears to the President that the public interests

would be served by the establishment of a Council charged with the duty of—

inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States ;

investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest ; or

making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject,".

मुझे दुःख है कि इस आर्टिकिल 263 में जिसमें एक इंटर-स्टेट कौंसिल बनाने की बात है वह अभी तक बन जानी चाहिये थी। यह आलरेडी ओवरडियु हो गई है और आयन्दा भी चूंकि कोई एक पार्टी की हुकुमत इस देश में चलने वाली नहीं है और राज्यों में आयन्दा भी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स बनने वाली हैं इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह की एक इंटर-स्टेट जोनल कौंसिलें बनें। इतना ही नहीं अपोजीशन की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी मैं यह भी चाहता हूँ कि इस तरह के रवायात हों इस तरह के कन्वेंशंस हों और इस तरह का कोड डेवलप करना चाहिये जिससे कि हारमोनियसली काम चले। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम युनिटैरी टाइप आफ गवर्नमेंट चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि स्टेट्स को और अधिक अधिकार मिलें लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि जो भी अधिकार उन्हें पहले से संविधान में मिले हुए हैं वह उन्हें उपयोग में ला सकें और मैं नहीं चाहता हूँ कि केन्द्र एक डंडा हाथ में लेकर मिनी-डिक्टेटर की हैसियत से उनके सिर पर सवार हो जाय। केन्द्र का एक इस तरह से डंडा हाथ में लेकर उनके सिर पर खड़ा हो जाना भी ठीक नहीं होगा।

आपने भाषा के आधार पर प्रान्त बनाये उसमें आपको बिलकुल मिजरेबुल फेल्योर हो गया और मेरा कहना है कि जो ऐक्सपैरीमेंट आप आसाम में कर रहे हैं और रिआरगनाइजेशन की वहां पर बात कर रहे हैं वह डिजास्टरस होगा और वह देश के लिए घातक सिद्ध होगा। आप चाहे आज हमारे साथ सहमत हो या न हों लेकिन हमें इस नेश के कामकाज को एक मुनासिब ढंग से चलाना चाहिये। उसे एक दूसरे के साथ मिल कर चलाना चाहिये।

अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वह फेडरल टाइप का स्ट्रक्चर है। यह फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से ही ज्यादा अधिकारों की मांग उठती है। कई बार यहां पर आजाद राज्यों के बनाने की भी बात उठती है। आज ही डी० एम० के० के मिनिस्टर की बात जो उन्होंने कही वह मुझे पसन्द नहीं आई। उन्होंने यह कहा कि अभी तक हमारी वह पुरानी डी० एम० के० की आजाद राज्य की मांग रद्द नहीं हुई है हालांकि चीफ मिनिस्टर ने उस बारे में जो बात कही मैं उन्हें इसके लिए बधाई देना चाहता है। लेकिन एक मिनिस्टर ने वैसी बात जो कही वह ठीक नहीं कही। उसने कहा कि आजाद डी० एम० के० की मांग अभी जिन्दा है...

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : You are wrong, Sir.

MR. SPEAKER : You can say that when you speak.

श्री कंवर लाल गुप्त : इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करूंगा कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वह फेडरल नहीं रहना चाहिये वह युनिटेरी होना चाहिये। मैं चाहूँगा कि आज दुर्भाग्य से हमारी सेंट्रल लीडरशिप की जो कमी है वह दूर हो और एक मजबूत सेंटर कायम हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह इस देश में मजबूत लीडरशिप प्रदान करे जो कि एक बेलेंस करके इस देश का कामकाज ठीक प्रकार से चलाये। पार्टीलाइंस का खयाल न करके वह देश के हित को ही अपने सामने रखे और राज्यों और केन्द्र के इस तरीके से संबंध बनायें और ऐसे कन्वेंशंस बनाये जिससे अभी जो हमारी डेमोक्रेसी है वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाये और मजबूत से मजबूत होती चली जावे व इस देश का नाम दुनिया के देशों में

[श्री कंवर लाल गुप्त]

ऊंचा हो । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

MR. SPEAKER : He has taken half an hour. There are seven parties in the Opposition and the spokesman of each one of them must be given time. Naturally, an equal number has to be given time on the Congress side also ; after all, they are more than 50 per cent on that side. That is what we are following. Therefore may I appeal to hon. Members to take about ten minutes each ?

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : 20 minutes.

MR. SPEAKER : That means, only one or two will speak and the others will not speak. That is what will happen.. If each one of them takes half an hour in a two-hour discussion, that is what will happen. If it is not possible, I cannot help it. How am I to distribute time among others ?

SHRI P. K. DEO : Extend the time.

MR. SPEAKER : It can be done only by half an hour or 45 minutes.

Even then, you will not get each one half an hour. If each one of you get 20 minutes, I have absolutely no objection. But I am rather worried I will be put into difficulty of ringing the bell. After all, 5 minutes this side or that sides will not matter. I am not giving all the 50 per cent time to the Congress Party because the Minister also takes away the time. Anyway, I would appeal to you to take, if not 10 minutes, not more than 15 minutes. Even then, 15 Members have to speak. You should take that into account. Shri R. D. Bhandare.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Speaker, Sir, I was both surprised and amused to hear the speech of my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta. This subject arose out of the demand for a discussion under Rule 193 because he wanted to discuss the Centre-State relationship in the context of attitude of the Kerala Government. That was the subject. But my hon. friend has spoken of philosophy of his Party, that he would like to have a unitary form of Government in India. The major portion of his speech was devoted to the pleading for a loose type of federation that he would like to preach. He has lost faith in majority rule and, I think, he has developed some sort of mini-skirt mania, because he started with the Rajasthan Government and ended the first portion of his speech on the mini-skirts. There was no reason whatsoever to deal with mini-skirts at all.

AN HON. MEMBER : You should not follow him.

SHRI R. D. BHANDARE ; Don't be under the impression that you will not.

I am coming to the point. The major portion of his speech was devoted to the defence of the action taken by Kerala Government and he said that Government had a right to intervene, right to send the Central Reserve Police Force, and, at the same time, he asked why the Kerala Government was not consulted before the CRP was sent. On that basis, he tried to defend the Kerala Government. Here is a case where the Jana Sangh and the Communists are found today as strange bed-fellows.

SHRI NAMBIAR : For a few minutes only ; then, my friends parted company.

SHRI R. D. BHANDARE : The major portion of his speech was directed to a loose form of federation. What the Communist friends what is that the Centre should be so loose, the federation should be so loose and states should demand more powers so that the Centre should be weak. And powers for what ? They want powers to destroy democracy they want powers to destroy the Constitution itself. Have I not heard Mr. Nambiar, very patiently, saying, "I do not believe in democracy at 11." ?

SHRI NAMBIAR : Of this type.

SHRI R. D. BHANDARE : The type of democracy that we have established is under the Constitution. That is the type...

MR. SPEAKER : You must also say what your view is.

SHRI R. D. BHANDARE : I am coming to that. I am going to tell them the constitutional provisions, the constitutional arrangements, that have been made in order to retain, maintain and preserve inter-State relationship, so that the unity of the country could be preserved.

I was really very surprised to hear my learned friend, Shri Kanwar Lal Gupta, reading out a portion of the speech of one of the Ministers of the Kerala Government and yet supporting that Government. From that I conclude that the Communists are more interested in a weak Central Government, more interested in a loose type of Federation, as Mr. Kanwar Lal Gupta is. Therefore, I said that they are today strange bed-fellows ..(*Interruptions*). I am certain that the Home Minister will take care of himself ; because of my speech I do not think that he will lose the case.

Now I come back to the original proposition whether the Kerala Government's action during the Central Government employees' strike was justified or not. It was not justified at all. Why was it not justified ? Once we have accepted Federation, so long as the Federation stands accepted, we have got to preserve the Constitutional provisions *in toto*. To deal with the Centre-State relations, the Constitutional provisions have first dealt with the federal principle itself. The powers are divided between the States and the Centre. This is one aspect of it. But our Constitution is not satisfied with mere division of powers. Our Constitution has also accepted provisions as to how the administrative relationship should be between the States and the Centre. This is the second and the most important point. Apart from the question of the division of powers, the spheres within which the States will operate, and the Centre will operate, even the administrative relationship is well-defined and incorporated in our Constitution. Then, our Faunding Fathers were also not satisfied with merely defining the administrative relationship, they have even defined the financial relationship, the distribution or devolution of finance .....(*Interruptions*) and the machinery by which the distribution of finance could be effected has also been provided in our Constitution, and that machinery is the Finance Commission; so, the machinery itself is incorporated in the Constitution. Then, there, are provisions about the High Court judges, the Public Service Commission, the Election Commission, the All-India Service, the SCST Commissioner, the institution of Governorship. Mr. Kanwar Lal Gupta dealt with this aspect as to why is it that Governors are not appointed in consultation with the States...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : never said that.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : He has not followed his speech at all.

MR. SPEAKER : The hon. Member has already taken ten minutes. He has only five minutes left.

SHRI R. D. BHANDARE : I will conclude in five minutes.

He mentioned the case of Bihar and, therefore, I have raised that question. Then, the provision for Inter-State Council, for inter-State water disputes is also there. These are the Constitutional provisions by which the good relationship, the workable relationship, between the States and the Centre could be preserved.

Sir, apart from the Constitution. .

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Which constitution ?

SHRI R. D. BHANDARE : Don't think I am referring to your constitution. I am referring to the constitution of India.

Sir, apart from the Constitution, the extra-constitutional relationship has been accepted ever since the constitution was adumbrated. How to preserve good relations between the Centre and the various States, apart from the constitutional provisions, is also a subject which has been dealt with. The National Development Council, for instance, has been able to retain good relationship between the various States and the Centre. There are various agencies like the Planning Commission which take care of the centrally sponsored schemes, formulation of plans etc. If the

[Shri R. B. Bhandare]

were to study the history of the federal Government all over the world, we have to take into consideration that in spite of the enumeration of powers, the balance is always tilting with the Centre, towards the Central Government. Why ?—because, there are certain inherent powers. There are certain implied powers. There are also certain residuary powers which lie with the Centre in the constitution itself and I need not elaborate on that point, as to what those powers are. The taxation system, the monetary system, foreign relation agreements, the State security as the time of external aggression and internal direction, are all subjects which lie with the Centre. Even under those circumstances the Centre has certain powers. In view of all this I would have certainly advised the Home Minister and the Central Government to take drastic action against the Kerala Government for not following the mild form of advice during the central government employees' strike. Sir, let the whole world know that the communists do take advantage of democracy. Let the whole world know that the communists take advantage of the constitution....It is a well-known fact. (*Interruption*).

SHRI NAMBIAR : The whole world knows very well. (*Interruption*).

SHRI R. D. BHANDARE : If I give a lecture on communists and communism, I do not know whether they have the patience fo hear me... ..

MR. SPEAKER : Both of you may agree ; but I have to ring the bell now.

SHRI R. D. BHANDARE : Still I have got two minutes more ; I am conscious of the time and I was concluding. Apart from the speeches of some of my hon, friends, even the action of the Kerala Government—clearly and glaringly—brings out their faith and their thinking, that they are not for democracy, they are not for the constitution.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Sir, the general election saw the rout of the congress party at the polls and the monopoly of the congress rule broken. With the emergence of various non-congress Governments in various States and the Congress strength being much reduced in the Centre the States-Centre relationship has taken a new dimension.

Sir, in a country which is multilingual and multi religious and various units are there having separate identity, perhaps, a federal type of Government is the only answer which implies division of power between the Centre and the States, which will give full scope to the various units to develop according to their genius in their autonomous way.

The Indian Constitution is not a federation in the strictest sense of the term as the States and the Centre should have the power and ability to function in their respective fields through their respective agencies. Even though the various subjects have been enumurated in different lists of the 7th Schedule, residuary powers rest with the Centre and any law made by a State in respect of any of the State subjects even will be inoperative to the extent of any inconsistency or conflict with the laws made by Parliament. In case of national emergency or breakdown of the constitutional machinery or mismanagement of State finances, Parliament can step in and assume the legislative powers of the State.

The Constitution, while it has divided the various legislative powers as between the Centre and States, does not envisage a separate agency for enforcing Central laws in the States. They have to depend on the State administration or State machinery for this purpose. Art. 256 makes it obligatory on the part of a State to comply with Central laws.

The Kerala Government's attitude in regard to the implementation of the Essential Services Maintenance Ordinance is one which is calculated to undermine not only the integrity and sovereignty of this country, but the very basis of the rule of law. Though we recognise the fundamental rights of some categories of government servants, of course excluding the army, police and members of the civilian administrative service, to strike for purpose of collective bargaining, I must say the strike of 19 September was a political

one and was politically manoeuvred, masquerading of course as an industrial dispute. Shri Masani has very nicely analysed the whole situation and I do not want to repeat it.

On 13 September, the Ordinance was promulgated empowering the Central Government to declare strikes in specified essential services to be illegal. Accordingly, instructions were issued to all States to take such appropriate action against instigators and offenders. On the very same day, the Kerala Chief Minister declared that he was not going to carry out the instructions of the Central Government. Four Ministers of the Kerala Cabinet blessed the strike and extended their full sympathy to it in public meetings.

SHRI S. M. BANERJEE : Congratulations.

SHRI P. K. DEO : In the circumstances, the Centre had no option but to send the CRP to guard central offices in the State, as the same time reminding the State Government of its constitutional obligations to comply with the law of the land, that is, the Ordinance at that time.

SHRI S. M. BANERJEE : Lawless law of the land.

SHRI P. K. DEO : When the Kerala Chief Minister spoke in clear terms of his intention not to comply with the Centre's instructions, the Centre could not remain a silent spectator and abdicate its own responsibility to safeguard central installations and to give protection to loyal workers against the wrath of the law-breakers. In fact, it was its duty to do so ; its deployment of the C. R. P. was therefore fully justified.

The question of propriety comes in. The Kerala Government might not have asked for the C.R.P. as the Orissa Government had asked when communal disturbance broke out in that State. But there is some limit to this.

How long could the Central Government be a silent spectator of all this drama? What Kerala did was to throw a challenge to the Central Government in exercising its constitutional duty and violated article 256 in very clear terms. The Centre did no more than enforce the ordinance.

Lately we are getting very grim reports, that a sub-inspector was speared to death and that some members of the State police force have been butchered in Kerala. How could a Government which could not protect its own police force, its own employees, give protection to the Central installations especially against the orders of the Kerala Chief Minister ? Subsequent events which have unfolded have revealed that it was a calculated move to spread lawlessness throughout the country to prepare the ground for foreign intervention. Fraternal help is always ready to come from certain countries. The precedent is there. We saw the Russians rushing to Czechoslovakia to suppress the humanisation, liberalisation, of their administrative system. I quoted that day from Mr. Nagi Reddy's statement to the students of Hyderabad preaching Mao's theory, the theory of enemy No. 1 of this country, who stated that power flows from the barrel of the gun. Whether it is Kanu Sanyal or whether it is Jangal. Santhal or Kunnikkal Narayan an, their activities and *modus operandi* are no better than those of the dacoits operting in the ravines of Chambal valley.

The only difference is that the former have extra-territorial loyalty and have got inspiration from foreign countries and from the enemies of this country. Any pretext is good enough for the Kerala Chief Minister to declare hostility against the Centre. I will not be surprised if even a pertial repudiation of the Treaty of Merger on the part of the Government of India sparks a demand for sepratism in Kerala and they may ask for the restoration of the *status quo ante*. We cannot forget C. P. Ramaswamy Ayyar's days when they wanted to declare Kerala independent. It was the iron hand of Sardar Patel which put it down with the willing cooperation of the Travancore Ruler which smoothened the integration of the States in India. I request that this should be examined from this aspect. As I pointed out, the sending of the Central Reserve Police is fully justified.

Taking advantage of this debate, I would like to focus the attention of the House on some important aspects of State-Centrerelationship. We stand for the maximum State autonomy. At the same

[Shri P. K. Deo]

time we have to respect the Central authority. It is a question of a cooperative federation, something of a matrimonial relationship. Even if they quarrel, it is a question of give and take, it is question of compromise, and they should extend a helping hand to promote the common interests. It should be examined in that perspective, but recent events are not encouraging for the promotion of happy relationship between the Centre and State. As pointed out by my hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta, the institution of Governor is being utilised as a lever to topple down non-Congress Ministries. No standard is being laid down for the conduct of the Governors I would like to quote from a speech of my distinguished friend, the late Shri H. C. Mathur. He said :

> "The Governor is the representative of the President in the State, but at the same time in political and administrative matters he is not an agent of the Government of India."

We saw in Madhya Pradesh when the Assembly was in session and was discussing the budget, it was prorogued on the advice of the Chief Minister who did not enjoy a majority at that time. In West Bengal the Governor insisted hastening of the State Asssmbly to be called. In Rajasthan the Chief Minister feared to face the Assembly and no attempt was made to form an alternative government even though the majority of the Members of the Assembly came here and paraded before the President and expressed their allegiance to the leader of the Opposition and the President's Rule was imposed. In Haryana a stable Ministry was toppled down and we are given long thesis on defection and public morality. But in the neighbouring State of Punjab one area defector was appointed Chief Minister, a minority Government with the support of the Congress. Not a day was given to Sardar Gurnam Singh to meet the Prime Minister when he came to Delhi. No prescribed standard has been laid down regarding the behaviour of the Governor. This has put the institution of Governor to shame. Guide lines should be provided regarding their behaviour. We find often encroachment on the State's autonomy. Industries primarily assigned to the State later declared by Parliament to be expendient in public interest come under the provision of the Centre. So also the mines and archaeological sites. But the worst comes when we go to the financial resources. That is why a constitutional provision has been made in the Constitution for this quinquennial Finance Commission because you know very well the functions and the resources of the State could not be matched together. Functions are many but the resources are limited. That is why the recommendation of the Finance Commission is necessary for the allocation of the central revenues and further provision also exists for statutory grants under Art. 275 and thirdly comes the discretionary grant under Art. 282 and lastly, loans for capital expenditure which is given to the various States according to the priority that is laid down by the Planning Commission. The first two are kept in the purview of the Planning Commission. But I would suggest that all these four things should be looked into by the Finance Commission.

Sir, the dependence of the State finance on central resources is on the increase. The total central resources transferred as a percentage of the States total expenditure in 1950-51 was only 30—30.3%. In the First Plan it rose to 41.8%, during the second plan it was 49% and in the Third Plan it was 53%. Taking into consideration this aspect, I must say that the interim report of the present Finance Commission has been most disappointing and depressing and arbitrary. In this regard instead of going into many aspects, I would like to pin-point on my State of Orissa. If you read the interim report of the Finance Commission, paragraph 60 and 61, you will see that the Finance Commission has accepted the forecast of the Central Government in toto. It has rejected the claims of the States on the ground that the estimated surplus of Central Government has fallen so much short of the total estimated portion of the States. This is not a happy situation because the legitimate claims of the States could not be ignored merely on the ground that the Central Government's forecast does not reveal adequate surplus funds for transfer to the State. In the case of Orissa the Finance Commission recommended the continuance

of the grant in aid at the existing level of Rs. 29.8 crores in spite of the fact that the revenue deficits are bound to be more than what led the previous Finance Commission to recommended this order of grant. There has been a very significant burden on the State on account of the revision of the dearness allowance. It is estimated to cost as Rs. 13 crores over and above the level of the expenditure on the basis of the recomendation of the previous Finance Commission. The economic condition is deriorating because of the rise in prices and inflation for which the Central Government is primarily responsible. The wrong economic policies pursued for the last 20 years are responsible to bring this mess. Why should the States be penalised for this ? Why should not the Centre bear a portion of the burden in this regard ?

Since the grant of such assistance is discretionary, and is so far not bound up on a statutory basis, autonomy of States is jeopardised. If the Central Government wants to discredit the State Government, it can decline to grant loan assistance to the State for enabling her to meet repayment liabilities, and then invoke article 360 regarding financial emergency on the ground that the State Government has failed to keep her financial commitments. The financial powers have been used by the Centre to impede the progress and to discredit the non-Congress State Governments.

17.00 hrs.

Further, the centralised planning has superseded the federal character of the Constitution and is functioning like a unitary system. In spite of the Central planning, in spite of being told time and again that the regional imbalance should be removed, it is on the increase. The difference between the *per capita* income of Orissa State, as compared to the national *per capita* income, was only Rs. 100 in the last fifties, and now the difference is Rs. 200 in spite of 15 years of planning. You can therefore very well realise what we are heading for, when the gulf of disparaty is widering in each plan.

The allocation of planning and priorities is being done on a partisan basis. Before I conclude, if the Constitution were to function property and if the States were to preserve their autonomy, I would like to quote from a nice observation made by Mr. Mohan Kumaramangalam in the Seminar held at Delhi. He says :

> "...the experience of countries like Canada was a clear indication that the unity of a country could be achieved more effectively by making the States more autonomous, since this ensured a better and more effective working of the Governments."

Before I sit down, I would like to quote a few lines from no less a person than Mr. K. Santhanam, who was the Chairman of the second Finance Commission, and also a Lieutenant-Governor and also a Member of the Constituent Assembly, in his address to the Indian Institute of Public Administration at Delhi. He said :

> "If at any time in the future, a considerable number of State Governments should belong to parties different from that which controls the Union Government or the Union Government finds it necessary to curtail drastically its financial assistance, there may have to be a reversion to State autonomy to the fullest extent provided by the Constitution."

I conclude my remarks with the following suggestions : firstly, the Inter-State Council, as suggested by Kanwar Lal Gupta, should be constituted under article 263 to go into all these matters. Secondly, instead of the Governor calling upon the leader of his choice to form the Government, he shall convene the Legislative Assembly and the Legislative Assembly should elect the leader of the House and only he is the person who should be called upon by the Governor to form the ministry. Finally, the Finance Commission should be made a permanent Commission to review from year to year the fiscal relations between the Centre and the States and who can dispassionately distribute the various revenues according to the needs and requirements of the States.

MR. SPEAKER : According to the group-strength, time is being allotted and that is what we have been doing. The other parties will also have the same proportion. Mr. Bohra.

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में जो आज चर्चा उठी है उसके बारे में जो बुनियादी बात है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चौथे आम चुनाव के बाद जो परिणाम आये हैं और जिस तरह की राज्य सरकारें बनीं उसके बाद केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की चर्चा एक विशेष प्रकार का वातावरण हमारे देश में बना। मैं इस समय आपका ध्यान थोड़ा इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमें वह दिन याद है जब मुहम्मद गौरी ने इस देश पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज और जयचन्द एक नहीं हो सके। हमें वह दिन याद है जब बाबर ने इस देश पर आक्रमण किया था और सांगा ने आह्वान किया था कि हम सब मिल कर इस देश की रक्षा करें लेकिन हमारा देश उस समय एक नहीं हो सका। हमें वह दिन याद है जब मुगल काल के अन्तिम दिनों में हमारे देश के सूबे स्वतन्त्र हो गये थे। हमारे देश में अलग अलग सूबे कमजोर पड़ रहे थे, केन्द्र कमजोर हो गया था और अंग्रेजों को बड़ी आसानी से हमारे देश पर कब्ज़ा करने में सफलता मिली। तो इतिहास के इस सबक को यदि हम ध्यान में रखें तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की स्वीकार करें कि हमारे सामने राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र एक है, यह हमारे देश के सूबे का यह मुख्य बात है जिसकी छाया में और जिसके परिवेश में हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

मैं अपने बहुत योग्य और कर्मठ गृहमंत्री का इस अवसर पर अभिनन्दन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस नाजुक समय में जब कि चौथे आम चुनाव के बाद हमारे देश की आन्तरिक स्थिति उभड़ कर सामने आ गई, कहीं नक्सलबाड़ी, कहीं केरल में कम्यूनिस्टों की हरकतें, कहीं बंगाल के अन्दर माओ-त्से-तुंग के चित्र, इन तमाम परिस्थितियों के अन्दर देश को नेतृत्व दिया और इस बात का सबूत दिया कि यदि सेंटर मजबूत नहीं रहेगा तो इस देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी। मैं, इसलिए बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूँ और मुझे दुःख है कि मेरे भाई श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने सिद्धान्तों और विचारों के विपरीत सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये एक ऐसे लूज़ फेडरेशन की चर्चा की, जब कि उनके जो नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने हमेशा इस बात की मांग की हैं, उन्होने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि केन्द्र मजबूत होना चाहिये, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखण्डता के लिए, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये केन्द्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन में आपसे कहना चाहता हूँ, जनसंघ की यह दृष्टि नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वह इस पिछले साल भर के दौरान में उनको जो एक मौका मिला उसको लेकर कहा। पिछले साल भर में देश के अन्दर कई प्रान्तों में कांग्रेस को अपदस्थ करके जिस प्रकार की सरकारें बनीं उन सरकारों में जनसंघ ने भाग लिया और ऐसे समझौते उनको करने पड़े, कहीं कम्यूनिस्टों के साथ, कहीं अतिवादियों के साथ, कहीं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ उन की विचारधारा मेल नहीं खाती, ऐसी स्थिति में जो खिचड़ी सरकारें बनीं उन सरकारों के प्रति केन्द्रीय सरकार दयावान नहीं हो सकती थी, करुणा नहीं दिखा सकती थीं क्यों कि जिस तरह की खिचड़ी सरकार बनी उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं था। तो अपने दोषों, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह की बात आज कही जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि सिद्धान्तों को त्याग कर जनसंघ और कम्यूनिस्टों ने मिल कर या अन्य विचार-धारा के लोगों ने मिल कर जिस तरह की सरकारें बनाई उन सरकारों का अन्त स्वाभाविक था। उनका इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं था। ...(व्यवधान)... मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आज केरल की सरकार को गिराने के लिए केन्द्र की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। उड़ीसा की सरकार को गिराने के लिए केन्द्र की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया जाता क्यों कि हम जानते हैं कि उड़ीसा की सरकार अपने ढंग से काम

कर रही है। डी० एम० के० की सरकार मद्रास में अपने बहुमत से अपने विचारों के अनुसार काम कर रही है। लेकिन जिन प्रान्तों में यह सरकारें समाप्त हुई, चाहे हरयाना हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो उन का इस के अलावा और कोई दूसरा परिणाम नहीं होना था। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में तो आप की ही सरकार चल रही है। वहां किस प्रकार प्रजातंत्र का तमाशा हो रहा है? मैं आप से पूछना चाहता हूं आप केन्द्र से क्या चाहते है? आप का आपस में विचारों का मेल नहीं है, आपस में मतभेद है। ऐसी सरकार के लिए आप केन्द्र से मदद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह सरकारें कायम रहें, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट में आने से पहले कांग्रेस ने वर्षों तक आजादी के लिए संघर्ष किया और तब सत्ता में आई। आप चाहते हैं कि बिना संघर्ष और सेवा के, आप सरकार में आ जायें। पहले आप जा कर जनता में काम कीजिए और जब आप का बहुमत हो तब सत्ता में आइए। लेकिन सिद्धान्तों को त्याग कर सस्ते समझौते न कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि इन खिचड़ी सरकारों के पतन के कारण राज्य और केन्द्र के सम्बन्धों के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसका मुख्य कारण यह है कि आप ने खिचड़ी सरकार बनाई, सिद्धान्तों को त्याग कर आप ने समझौते किये ताकि आप सत्ता में आ जायें। इस लिए मैं कंवर लाल गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि खिचड़ी सरकार बनाने के बनिस्बत आप सिद्धांतों पर डटे रहिए। जनता अगर आप को बहुमत दे तो आप गवर्नमेंट बनाइये। लेकिन जब आप सिद्धान्त को त्याग कर सरकार बनाना चाहेंगे, तो केन्द्र आपके प्रति दयावान बने, अपने राइट को भूल जाय, यह सम्भव नहीं है।

आपने राजस्थान का जिक्र किया—आप को याद है कि दौसा के उप-चुनाव में महारानी गायत्री देवी का लड़का पराजित हुआ, झालौर में भी अभी अभी आप हारे हैं—यह किन बातों का संकेत है यह इस बात का संकेत है कि स्वतन्त्र पार्टी और महारानी गायत्री देवी... ...(व्यवधान)...का प्रभाव वहां से समाप्त हो रहा है। अगर वास्तव में स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ का राजस्थान में बहुमत होता तो ऐसा नहीं होता। किस तरह से प्रलोभन देकर रानी गायत्री देवी ने, सामन्ती नेताओं ने, पैसे के बल पर अपने राजप्रसादों में, किलों में विधान सभा के सदस्यों को दबा कर रखा, लेकिन इस का परिणाम यह हुआ कि जब उनको जनतन्त्र की हवा मिली, सब उन को छोड़ छोड़ कर कांग्रेस के साथ आ गये – जिस का ताजा उदाहरण ये दोनों उप-चुनाव हैं। आप हवा के रुख को देखिये, राजस्थान में जो भी उप-चुनाव हुए उन में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। इस लिए यह कहना कि राजस्थान में जनतन्त्र की हत्या हुई है या राजस्थान के साथ केन्द्र ने अच्छा सुलूक नहीं किया या कांग्रेस ने अपना बहुमत बनाने के लिये ऐसा किया—यह सब भूल है, प्रबंचना है, अपनी शक्ति को जरूरत से ज्यादा समझना है।

17.11 hrs.

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*.]

केरल के बारे में भी दो शब्द मुझे कहना है। केरल में केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर केरल सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया और हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, उस के लिए मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं। इस लिये अभिनन्दन करना चाहता हूं.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या दृढ़ता दिखाई? ...(व्यवधान)...

श्री ओंकार लाल बोहरा : यह प्रश्न केवल केरल का नहीं था। यह प्रश्न उसी तरह का था जिस तरह नक्सलवाड़ी के अन्दर, पश्चिमी बंगाल के अन्दर कुत्सित षड्यन्त्र चल रहा था, उस समय भी केन्द्रीय सरकार ने जिस दृढ़ता के साथ कदम उठाया था और जिसका हम सब ने समर्थन किया था, उसी तरह...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कदम उठाया था?

श्री ओंकार लाल बोहरा : राष्ट्रपति शासन जिसकी माँग बंगाल की जनता ने की थी।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम देश की एकता को कायम रखना चाहते हैं—मैं खास तौर से वाजपेयी जी और कंवर लाल गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूँ—यदि आप देश की अखण्डता की बात करें तो अपने दिमाग से भ्रान्तीयता को दूर रखना चाहिये। केरल में केन्द्रीय सरकार ने जो रुख अपनाया है, वह राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, अखण्डता की दृष्टि से, केन्द्र का महत्व बना रहे, केन्द्र शक्तिशाली हो, उस दिशा में उचित कदम था। इस लिये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न उठाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है—यह इस बात का द्योतक है कि हम इस देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना चाहते हैं या नहीं, हम इस देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहते हैं या नहीं, वास्कोडीगामा सब से पहले कालीकट में उतरा था, लेकिन क्लाइव और हेस्टिंग्ज सब से पहले बंगाल की धरती पर आये थे। इस लिये हम चाहते हैं कि देश की एकता मजबूत हो। हम अपने पुराने इतिहास से सबक लें और जैसा हमारे भाई नम्बियार कहते हैं कि हमारी कालोनीज हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में आप प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तो आप अपने आप में निरीक्षण करें कि आप प्रजातन्त्र के ढांचे में देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यह समझते हैं कि आपको देश के प्रजातन्त्रीय संविधान में दिलचस्पी नहीं है तो मैं नहीं समझता कि इसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें केन्द्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए दृढ़ता से केन्द्र का समर्थन करना चाहिए।

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South) : Mr. Deputy Speaker, Sir, today we are discussing a problem, the problem of Centre-State relations, which may dvelop as a major crisis very soon if it has not developed already. Some years ago any discussion about the Centre-State relations in this august House would have been considered as a piece of anachronism because, as my hon. friends have pointed out, at that time we had a monopolistic dominance of a single party at all levels of government and, as Shri Gupta has pointed out, we had the towering personality of Nehru also. At that time any problem of the Centre and the States remained as a problem of constitutional law and a matter of academic interest. Today it has become a political problem and a problem of day-to-day politics.

It is very unfortunate that the Ordinance, which was promulgated to meet the circumstances of a temporary phenomenon, the one-day token strike of the Central Government employees, should have created a permanent source of misery to thousands of people and left indelible smudges on the fabric of our federal system

The entire controversy between Kerala and the Centre revolves around three points. Questions are being asked whether the Centre should consult the States before promulgating an Ordinance ; in issuing a directive if the Centre has discretion to arrest some persons and leave some other persons, whether the State also has got the same discretion ; and whether the Centre can deploy the Central Reserve Police in a State without its knowledge.

As the Chief Minister of Kerala, Shri Namboodiripad, has said, nobody questions the legal and the constitutional validity of the Ordinance. Everybody is aware of the rigours of the directives of the Union Government which demand implicit and instantaneous obedience to union laws. Similar powers are there to issue directives to the States with regard to the welfare of the Scheduled Tribes, the education of the minorities, the Union official language and so on. Any State can disobey them only at the risk of constitutional punishment. There is article 365 under the heading "Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union" and any refusal by the State Governments is equivalent to the breakdown of the constitutional machinery and

the ever ready Presidential rule may be clamped on the State. This is something special to our Constitution the like of which is not to be found in any federal constitution evolved in the world. It is a sword of Damocles which is hanging over the heads of States.

What will happen if the directive is in the form of a lawless law which infringes the very fundamental rights of a citizen ? Such a question was asked and discussed at a symposium on the All India Radio and the famous jurist, Shri Setalvad, has said that even in that case the State has no alternative but to obey it. But I think that there may be an alternative viewpoint also. It is for the constitutional pundits to go into that. Yet these are all in accordance with the letter of the Constitution. But I want to ask : Are they in consonance with the spirit of the Constitution ?

Let me quote one example. According to article 123 the President can promulgate an Ordinance during the recess of Parliament. How shall he exercise his powers ? Of course, on the advice of the Council of Ministers of the Union Cabinet. Let us imagine a hypothesis that tomorrow we have a President, who wants to act as the President of America and issues an Ordinance even without the advice of the Council of Ministers of the Union Cabinet. What shall happen ? Definitely we do not want such a situation, but there is nothing written in the Constitution to say that the President should promulgate an Ordinance only on the advice of the Council of Ministers.

Healthy conventions demand that the President should carry out these kinds of duties on the advice of the Council of Ministers. Our stand is that the very same healthy conventions demand that the Central Government should consult the States before promulgating an Ordinance.

This problem today is between a Congress Centre and a non-Congress State.

But tomorrow it may change and *vice versa* may happen. It is not an impossible thing that tomorrow there may be a non-Congress Centre and the Congress State. I want to pose a question to Congress friends in that situation and in this context. Would they want to be consulted before an Ordinance is proclaimed or not ? Would they want to be informed befor the Central Reserve Police Force is deployed to the State or not ? I would like my Congress friends to look into the problem from that point of view.

After the Fourth General Elections, everything has changed. The political set-up has changed in our country. Our experiment with federalism started only after the Fourth-General Elections. So, we have still to evolve democratic feelings, traditions and conventions. But what is happening is otherwise. The law and order has been considered as a privileged preserve of the States. But for the first time in the history of free India, this Government has deployed the Central Reserve Police Force to a State even without its knowledge. When our learned Law Minister was asked about it on September 23, 1968 at Cochin, he replied that the presence of C.R.P. in Kerala was rather symbolic. Symbolic of what ? It is symbolic of the inherent passion of this Government to topple down all non-Congress Ministries in India ? Is it symbolic of the desire of the Centre to become the ring master so that the States may perform at the crack of the whip ? I do not want to blame individuals for this.

It is a part of the attitude of the Empire building which is permeating the atmosphere of New Delhi. It is the result of the Constitution and that is to be blamed. In our Constitution, there is a built-in complex of perpetual Centre-State conflict. If law and order breaks down in a State, the Centre intervenes in the form of the President's Rule. If law and order breaks down in a Union Territory, such as, it happened during the policemen's strike and the anti-cow-slaughter agitation in New Delhi, and if law and order breaks down in a State which is under the President's Rule who will intervene ? Whether Gen. Kumaramangalam with his army will intervene is a question I want to pose before this Minister ? There is something inherently wrong in our Constitution. In my language there is a proverb that if a pot is broken by mother-in law, it is a mud pot and, if the same pot is broken by daughter-in-law, it will be considered as a golden pot and a lot of hue and cry will follow. Our Constitution is such that the Centre considers itself as an irate, termagant mother-

[Shri Murasoli Maran]

in-law and the States are concerned as docile daughters-in-laws.

AN HON. MEMBER : One day daughter-in-law will become mother-in-law.

SHRI MURASOLI MARAN : In Britain, the King can do no wrong. In India, the philosophy is that the Centre can do no wrong.

SHRI NAMBIAR : The Home Minister.

SHRI MURASOLI MARAN : There is the disbelief or lack of faith in the States. The Constitution itself does not believe the States ; there is lack of faith in States. Any estranged relationship between the Centre and the State is due to the shortcomings inherent in our Constitution.

I would like to quote here what the ex-Chief Minister has said about the Centre State relations. These are the words of the ex-Chief Minister of the biggest State in India. Let me quote :

> "There is less and less inclination to treat State Governments as partners in a common endeavour in a growing inclination to treat them as subordinates and agents whose outlook is normally narrow and who cannot be trusted to take important decisions by themselves."

These are the words of Dr. Sampurnanad in his book. "Memoirs and Reflections" written some six years ago. We all know he belongs to the biggest State in India which has supplied all the Prime Ministers of free India and more number of Union Cabinet Ministers and Governors. If such is the position, what will be the position of other non-Congress States I wish to point out.

This Government followes the letter of the Constitution like Shylock followed the letter of the bond. We are yet to know why the Inter-State Council as provided by article 263 of the Constitution has not been set up. I want to know the reasons for the same. There is another proverb in my language that the unseen legs of a snake are visible only to another snake. Like that, the mind of the Congress Minister is better known to another Congress Minister.

I want to quote the words of an ex-Minister explaining why such a Council has not been set up. I am quoting from the speech delivered at the Harold Laski Institute of Political Science in Ahmedabad on October 20, 1967 :

> "Probably this is because there is a fear that, in an inter-State Council, the Governments of the Union and the States will have equal status and there will be no scope for Central domination."

There are the words of our ex-Minister Shri K. Santhanam. I want to know whether this is the reason for not setting up the Council. That is why, we urge for the appointment of high-powered Commission to examine the Constitution vis-a-vis the relationship between the Centre and the States and suggest reallocation of powers facing the realities.

When we plead for a minimal Centre, at the same time I want to establish that we are second to none in maintaining the integrity and unity of India. Let there be no dobt about this. That is why we want that such powers that are essential for the maintenance of the integrity and unity of India to be vested in the Union, and the the others should be re-allocated to the States.

In the years to come, in future, there will be a polarisation of all political parties in India on this basis of changing this farce of federalism to create a real federalism. In the meanwhile, I wish to bring to the notice of the hon. Minister the learned advice of Shri Gajendragadkar, ex-Chief Justice of India :

> "Healthy Centre-State relations must be evolved wisely and not in a partisan spirit if democracy and federalism are to succeed in this country."

Therefore, in the interest of the country, in the interest of the unity of the country, I request the hon. Minister to stop the cold war which is being waged on Kerala.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : **डिप्टी स्पीकर महोदय,**

बात जो दिल से निकलती है असर रखती है,
पर नहीं, ताकते परवाज मगर रखती है।

इतनी गहरी बात सदन के सामने पेश है लेकिन अफ़सोस है कि इतने हलकेपन से इसको लिया गया। जैसे मेरे दोस्त ने भट्टा विठा दिया जनसंघ का वह प्वाइंट पेश करके। आज मुझे श्री कंवर लाल गुप्त से बड़ी मायूसी हुई। कहां गई उनकी देशभक्ति की ठेकेदारी ?... (व्यवधान)...कश्मीर का इन्टिग्रेशन, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, सारा मशिरकी हिन्दुस्तान खोखला हो गया है...(व्यवधान)... सवाल यह है कि अशोक के समय में यह देश एक हुआ था और फिर ढाई हजार साल के बाद हमारी खुशकिस्मती से सारा देश एक सूत्र में बंधा है। और ये लोग जो बैठे हुए हैं माओ त्सेतुंग के चेले चपटे, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। साढ़े सात सौ स्टेट्स इंटिग्रेशन हमारे सरदार पटेल और कांग्रेस के लीडरान ने किया था लेकिन ये लोग फिर से 1500 स्टेट्स बनाना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को हम होने नहीं देंगे। हमारे होम मिनिस्टर, चव्हाण साहब और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस देश के ऊपर एक अहसान किया है, टु निप दि इविल इन दि बर्ड, ताकि एक कांटा बड़ा होकर सारे देश को कहीं नासूर न बनादे, इन्होंने उस चीज का गला पकड़ लिया है। यहां पर तो सिर्फ केरल की बहस है फिर आप लोग चारों तरफ़ क्यों घूम रहे हैं ? आज केरल में जो जज़बा काम कर रहा है वह यह कि इस देश के विधान को कायम रखना है या नहीं रखना है, इस देश का झंडा कायम रखना है या नहीं रखना है, देश में डिमोक्रेसी को कायम रखना है या नहीं रखना है, इस देश की यूनिटी को कायम रखना है या नहीं रखना है, इंसानियत को कायम रखना है या नहीं रखना है और इस देश में प्रजातंत्र को कायम रखना है। या नही रखना है। आज देश के सामने मौजूदा सवाल यह है। लेकिन बनर्जी और उनके चेले चपटे इस देश को तहस-नहस करना चाहते हैं।

यहां पर कांग्रेस पार्टी या और किसी पार्टी का सवाल नहीं है। इस देश के 50 करोड़ आदमी आज यह चाहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर इस देश की युनिटी पर आंच नहीं आने दें। इस देश का कोई भी हिस्सा कमजोर न पड़े। आज देश का हर एक आदमी यह चाहता है कि हर कीमत पर इस देश की एकता कायम रक्खी जाय और जाहिर है कि वह मजबूत सेंटर होने से ही कायम रह सकती है। देश का कोई भी हिस्सा, कहीं पर भी कोई डिस्रप्टिव फोर्सेज अगर इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं तो ऐसी डिस्रप्टिव फोर्सेज का खात्मा किया जाय और सेंटर द्वारा उसका सिर कुचल दिया जाय। इस नाते मैं समझता हूं कि उधर के हमारे भाई नाम्बियार साहब ने जो बात कही वह कोई छोटी बात नहीं है कि उसे दरगुजर कर दिया जाय। उधर के वह भाई बार-बार यह कह चुके हैं कि वह इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को एक मजाक समझते हैं। इस संविधान को वह एक मजाक समझते हैं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को वह एक मजाक समझते हैं और इसलिये हमें उनके दिमाग में जो शरारत काम कर रही है उससे खबरदार रहना है और ऐसे डिस्रप्टिव एलिमेंट जहां भी हों उन्हें हमें मजबूती से टेकिल करना है। इसे खाली 19 सितम्बर की हड़ताल की समस्या ही हमें नहीं समझना है बल्कि यह देखना है कि सेंटर की रिट सभी जगह देश भर में चलती है या नहीं। अब यहां पर केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिये एक मामूली आर्डिनेंस पास किया और वह केरल की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसे नहीं मानते हैं। अब इस तरह की किसी भी राज्य सरकार के निदेश की अवहेलना करना एक बड़ी गम्भीर बात है। अब चव्हाण साहब या सेंटर कोई रिट जारी करे और पंजाब उत्तर प्रदेश या हरियाणा की राज्य सरकारें कहें कि हम उसे नहीं मानेंगे तो इस देश का क्या बनेगा ? इस लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारा सेंटर मजबूत हो। मुझे अफसोस है कि श्री कंवरलाल गुप्त कैसे इस बात के मुखालिफ हो गये...

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सेंटर मजबूत नहीं होना चाहिये। मैंने

[श्री कंवर लाल गुप्त]

तो हमेशा यही कहा है कि सेंटर को मजबूत होना चाहिये। माननीय सदस्य जो मेरे लिये इस तरह की गलत बात कह रहे हैं यह उचित नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि सेंटर मजबूत नहीं होना चाहिये।

श्री रणधीर सिंह : माननीय सदस्य को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। उन्हें दूसरा न्यु प्वाइंट भी सुनना चाहिये। आज की उन की स्पीच एक निराशावादिता की स्पीच थी। आज तक मैं श्री कंवर लाल गुप्त को हरियाणे का अपना एक भाई समझता था लेकिन आज से मैंने उन को बतौर हरयाणे के अपने एक भाई के तौर पर अपने दिमाग से निकाल दिया। इससे बढ़कर अफसोस की और कोई बात नहीं हो सकती है कि हरयाणे के आदमी के मुंह से देश को कमजोर करने वाली बातें निकलें। मैं तो श्री कंवर लाल गुप्त के मुंह से यह सुनना चाहता था कि सेंटर मजबूत होना चाहिये और श्री चव्हाण ने बतौर होम मिनिस्टर के जो कुछ किया वह ठीक किया। केरल में जो कम्युनिस्टों को लेकर और उन चीन के माओत्से तुंग के भतीजों को जिस तरह से रगड़ा वह उन्होंने ठीक किया। मुझे आज उनकी बात सुन कर बड़ी हैरत और साथ में दुख भी हुआ क्योंकि होम मिनिस्टर ने जो कुछ किया वह कोई कांग्रेस के लिए नहीं किया बल्कि इस देश को मजबूत बनाये रखने और इस देश की एकता कायम रखने के लिए किया था। श्री कंवर लाल गुप्त को मजबूत सेंटर के लिये कहना था ताकि इस देश में कोई विघटन कारी शक्तियां न पनप सकें और देश की एकता कायम रह सके। उस तरह की अव्यवस्था और कमजोर सेंटर जैसा कि बहादुरशाह या औरंगजेब के अंतिम काल में था वैसी नौबत आज न आ पाये। क्या हमारे श्री कंवर लाल गुप्त यह चाहते हैं कि जिस तरह से बहादुरशाह के जमाने में मुगल शासन लालकिले में महबूद हो कर रह गया था और मुगल शासन के अंतिम दिनों में मुगल बादशाहों की रिट लाल किले के बाहर नहीं जाती थी वैसी हालत आज बन जाय और सेंटर की रिट प्रान्तों में न चले ?...

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय सदस्य मालूम पड़ता है कि जब मैं बोल रहा था तब वह सो रहे थे अन्यथा इस तरह की गलत बात वह मेरे लिए कदापि नहीं कहते।

श्री रणधीर सिंह : मैं श्री कंवर लाल गुप्त को आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट मौजूद है क्या तो वह खुद या डी० एम० के० अथवा और भी कोई भाई जो भी इस तरह से सेंटर को कमसोर करना चाहेंगे और देश की आजादी और एकता को अगर कोई खतरा होगा तो केरल में जैसा सेंटर ने किया और जगहों पर भी अगर आवश्यक हुआ तो सेंटर मजबूत कदम उठायेगा। जो भी इस देश की एकता को चैलेंज करेगा, इस देश के संविधान को और इस देश की युनिटी व सौलिडैरिटी को चैलेंज करेगा उसे हमारे चव्हाण साहब रगड़ देंगे। हमारे चव्हाण साहब जो भी कार्यवाही करेंगे वह कांग्रेस पार्टी के हित की दृष्टि से न करके सम्पूर्ण देश के हित को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे।

बस एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। हमारे भाई ने इलाहाबाद की बात कह दी। अब इलाहाबाद या रांची का क्या इससे ताल्लुक था ? लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद और रांची में जो कुकर्म हुआ जो गड़बड़ हुई उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। मैं अपने दोस्त श्री कंवर लाल गुप्त को कहना चाहूँगा कि अगर उनकी पार्टी में से यह कम्युनलिज्म निकल जाये तो वह उनने ही बढ़िया हो सकते हैं जैसे कि यह कांग्रेस है। यह कम्युनलिज्म वह अपने में से निकाल दें हकीकत यह है कि वह उसे निकाल नहीं रहे हैं। दरअसल यह लोग कम्युनलिस्ट्स और सरमायेदार हैं और जिसे भी इस देश का हित प्यारा है वह कभी इन का साथ नहीं दे सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री रणधीर सिंह : बस मैं एक मिनट में खत्म किये दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस को और ज्यादा मजबूत करने के लिये हमारे चव्हाण साहब और अधिक अधिकार अपने हाथ में लें क्योंकि इन दोस्तों के जो मंसूबे हैं वह उन्हें बखूबी मालूम हैं और देश की एकता को बनाये रखने का जहां तक ताल्लुक है उस बारे में उन्हें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिये।

अब अमरीका में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और वहां अमरीका में फेडरल पुलिस व फेडरल आर्मी है। आपको मालूम है कि वहां अमरीका में जो कि अपने को डेमोक्रेटिक कहता है वहां पर अगर कोई स्टेट इस तरह से बदमाशी करे, चाहे वह नीग्रोज के मामले में करे या और किसी बात में करे तो वहां का सेंटर उसे रगड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सी० आर० पी० को और अधिक मजबूत किया जाय और जो भी इस देश की एकता को आँच पहुंचाये चाहे वह शेख अब्दुल्ला हों, नम्बूदरीपाद हों, या नागालैंड या मीजोलैंड ऐसी कोई भी चीज हो तो उन्हें मजबूती के साथ सी० आर० पी० के जरिये सेंटर टेकिल करे। इसके लिये बम्बई से एक आदमी खुद लिखता है कि अगर यह बात नहीं की गई तो हिन्दुस्तान की एकता को खतरा है और मौजूदा सिस्टम को तोड़ कर इस देश के चार हिस्से बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमें देश को और सेंटर को मजबूत बनाना होगा। यह ठीक है कि कांग्रेस गवर्नमेंट और चव्हाण साहब ज्यादा से ज्यादा लिंगविस्टिव बेसिस पर आटोनमी देना चाहते हैं लेकिन अगर वह उसे मिस्यूज करते हैं तो उन्हें रोका जायेगा और हम किसी भी हालत में सेंटर को कमजोर नहीं होने देंगे और हम ऐसी डिस्रप्टिव फोर्सेज पर रगड़ा चढ़ायेंगे। हम इस देश की एकता व हित को सर्वोपरि अपने सामने रक्खेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, तीन कांग्रेस के मेरे भाई बोले। दोनों ने यह कहा कि मैंने कोई लूज फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही है लेकिन उनका ऐसा कहना एकदम गलत है। मैंने तो साफ कहा मैं एक मजबूत सेंटर के हक में हूँ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : If three members had the same impression, he had better examine his own speech. I cannot permit him to convince them now. Every member had listened with great patience and attention. No more explanation is called for.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने तो युनिटरी फौर्म आफ गवर्नमेंट की बात की है। माननीय सदस्य मालूम पड़ता है कि उस समय सो रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद का जिक्र किया लेकिन मैंने इलाहाबाद की बात ही नहीं की।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peerwade): I am not a legal expert, but I am speaking on the basis of the bitter experience of my State and my people. The hon. Home Minister stated the other day that he always goes by the spirit of the Constitution. I wonder who is bothered about the spirit of the Constitution. At least as far as this Government is concerned, we are convinced by our experience that they are never bothered by the spirit of the Constitution. On the other hand, right from 1957—the story begins from 1957, not from 1967—our experience had been that the leaders at the Centre and the Government at the Centre had done everything possible to subvert a legally constituted Government in the State of Kerala.

AN HON. MEMBER : Question.

SHRI VASUDEVAN NAIR : Now, after 1967 also, my charge against the Central Government is that they in every possibly way are assisting and abetting all the forces at work in toppling that legally constituted Government in my State. I am making this charge with full responsibility.

In this nefarious activity, the Central Government have assigned a very important role to one of their Ministers in the Cabinet, the Law Minister, Shri Govinda Menon. It is not a pleasure for us, coming from Kerala, always to find fault with him ; he is the only hon. Congress member elected from Kerala to this Parliament,

AN HON. MEMBER : That is why he is opposed to him.

SHRI VASUDEVAN NAIR : He has the privilege to represent that once glorious organisation, the Indian National Congress, from Kerala in the 1967 elections, in this Parliament.

But his recent speeches, his recent activities as Union Law Minister—we are not concerned about the activities of Shri P. Govinda Menon—have been unlawful, and the Kerala Government have taken serious objection to his speeches and activities. They have brought it to the notice of the Home Minister and the Prime Minister and the Government of India that they should take serious notice of his activities, He is constantly exorting people for collective self-defence against the so-called violence of the ruling party in Kerala, the Marxists. On 3rd November he urged his partymen at Trichur that they should all resort to sticks,—he does not think of other weapons, he only thinks of sticks—to take the law into their own hands. If the Union Law Minister himself begins to exort people to organise collective self-defence and take the law into their own hands and then if he begins, to say that he is honouring the spirit of the Constitution, it is nothing but hypocrisy.

The Home Minister in a letter to the Chief Minister—I have no time to read it, otherwise I would quote it—has tried to give an excuse for not consulting the Kerala Government before sending the C.R P. All sides of the opposition I think, except perhaps the Swatantra Party members, including my hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta, are agreed that at least the Central Government ought to have consulted the Kerala Government before they despatched the C.R.P. So, in the letter to the Chief Minister, the Home Midister explains that he did not have enough time to do that. Is it a serious enough explanation for the Home Minister of the Government of India to say that there was not enough time to consult the State Government ? Of course, he also says that he has got the authority. That he always asserts, that it is not necessary to consult. That point is always there.

My only request to this Congress Government is this. Let them not declare too much from the housetops. We know what they are by their professions, by their practices, but they try to hide their activitives, their real colour, the real face, by tall professions, but we want to tear this mask from their faces. I want to say that in our State of Kerala as well as in many other States, all along after 1967 they have been doing everything possible to topple the non-Congress Governments. My hon. friend had gone over the entire scene after 1967, and I do not want to go over the entire subject again. We know what happened in West Bengal, we know what happened in many other States, we know what is going to be the fate of other Governments like the Tamil Nadu Government and other Governments They are coming. Now the main target is the Kerala Government. They want to finish the Kerala Government and then concentrate on other Governments. So, this is part of a conspiracy which the Central Government has hatched right from 1967. That is how I look at this matter. There is no point in dabbling in constitutional niceties and legal terms in this matter.

Let us face facts as they are. So, the question is whether the Central Government is prepared to put up with State Governments that have adopted entirely different policies, political, ideological and economic. The fact remains that during the last 20 years the Government at the Centre has come to represent in this country a lot of vested interests, monopolists and landlords and black-marketters and the worst elements in the Indian society. There were occasions in India, may be only for a few months, 28 months in 1958-59, our Government was there and it was short-lived. We are not afraid of it because we are facing a big challenge. We know because they have got powers in their hands, they have got their army, they have got their C. R. P., they have got sections and articles in the Consiitution. We knew that we represent something very different from what they are representing. This is the trouble. The trouble arises from the situation. At present the agitation in Kerala against the State Government has been intensifed of late because the State Government has gone in for a very important piece of legislation. It happened in

1957. The land reform Act is there. A Bill is on the agenda. Then the affected people are up in arms. Certain sort of people who will be affected by this are up in arms. The University Bill is on the agenda and is being debated in the legislature. The private colleges management. churches and all the vested interest in the field of eduction are up in arms.

AN HON MEMBER : There is Man Nath Padmanabhan.

SHRI VASUDEVAN NAIR : Man Nath Padmanabhan cannot do now. They have no captain to lead them now. They had one in 1957. So these people are now up in arms. Now these people always talk about secularism. Mr. Bhandare talked about strange bed fellows, Communists and the Jan Sanghis and I may tell Mr. Chavan that there are strange bed fellows in Kerala to-day where the Congress and the Jan Sangh are bed fellows now. Why ? Because they even want to make use of certain issuses to incite communal tension in Kerala. I charge the KPCC leadership of deliberately trying to foment Hindu-Muslim riots in Kerala, Hindu-Muslim tension in Kerala They want to make use of them so that the Government is discredited. There is a law and order problem created. Wherever there is trouble they poke their nose into the situation.

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member should conclude.

SHRI VASUDEVAN NAIR ; Sir, we are in the dock. The motion specifically refers to something which happened in Kerala. So you shonld be a little indulgent.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am already.

SHRI VASUDEVAN NAIR : I am thankful to you. Temple issues and other such communal questions are even utilised for working up the feelings of the people. What are the responsible leaders doing about ? They may be be here saying that they have nothing to do with that. What are their followers doing ?

Have they no control over them ? Now Sir, this particular September 19 crisis came. What happened in Delhi and Kerala Most of the K P C C leaders were flying daily to Delhi, almost everyday, coming and going and coming and going. In the Jantar Mantar there was a camp set up for the Kerala Congress leaders. They were refugees here before Mr. Chavan, before Mr. Govinda Menon and waiting for the Prime Minister, Smt Indira Gandhi, to return from here pilgrimage to Latin America. This is the best opportunity because they have violated the Constitution. because they have violated the orders from the Central Government. This is the best opportunity to dismiss them and I may tell you, Sir, that some people in the Home Ministry were briefing the newspapers that this is a subject under discussion in the Centre between the learders in the Cabinet every day. What is the news ? The Kerala Government may be dismissed any day. Such things appeared.

What will happen among the officers in the State Government when such news appears. Because it is the leaders of the ruling party at the Centre who are now demanding the dismissal of the Government and they are spreading these things in their newspapers. So, this is the situation that is existing and how can a State Government in this situation, function with stability ? You talk of autonomy of States, the rights of States, the powers of a State. This is a conerete situation that obtains in this country ; this is going to be the fate of many other States in India. This is not going to be the fate of the Kerala State only ; this is going to be the fate of even Maharashtra if Maharashtra is going to have perhaps a different way. Perhaps it is going to be fate of many, many other State Governments, and people in India. That is how we are concerned about the situation.

So, we want the whole country, this Parliament, to take note of this situation that has come up, as a result of the new developments following the 1967 general election. I wholeheartedly support the suggestion made by the mover of this motion, namely, the Inter-State Council, and I also support wholeheartedly the suggestion made by my friend Shri Murasoli Maran to have a high-power commission to go into the entire question. Let us try to straighten out the issues so that the people who want to topple the governments which represent the people of this country are not at the mercy of these people, so that they would

[Shri Vasudevan Nair]

be able to function with stability as long as those people want those governments to function.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) *rose—*

SHRI INDRAJEET GUPTA (Alipore): Sir, after this very convincing speech, may I know what action will be taken against the Law Minister ?

SHRI GOVINDA MENON : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I did not want to intervene in this debate ; I would not have done so—

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Is he tendering his resignation or what ?

SHRI GOVINDA MENON : I would not have intervened in this debate but for what Shri Indrajit Gupta considered to be a convincing speech from Shri Vasudevan Nair. It was not so convincing to me, and I wanted to say that. First of all, I want to repudiate and repudiate strongly the allegations made by Shri Vasudevan Nair against me.

SHRI S. M. BANERJEE : A Commission should be appointed.

SHRI GOVINDA MENON : I want Shri Banerjee and others in the House to know what exactly I have said. I stand by what I have said and I have absolutely no difficulty to repeat it. Sir, I have charged the Government in Kerala, particularly the Chief Minister, that when members of the Marxist party attacked people, committed aggression, the police would be conspicuous by their absence in that situation. (*Interruption*). Please listen. Even if complaints are made, there is no use. (*Interruption*).

SHRI NAMBIAR : Is it the duty of the Central Government to say that (*Interruption* .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Some changes have been made and he is replying.

SHRI GOVINDA MENON : This is the complaint which even Shri Vasudevan Nair and his party have in Kerala. It was only a week earlier that all the members of the right communist party in the Kerala legislature walked out in protest against the policy of the Chief Minister, because there was a lathi charge against the workers belonging to the right communist party. The Chief Minister promised to institute an investigation ; he refused to do so and today, two or three members belonging to Shri Vasudevan Nair's party, the right communist party, are reported to be on a hunger-strike, because, the Government there, the Chief Minister, is not behaving rigthfully towards the activities of the right communists. And one of two days earlier, seven to eight members belonging to the revolutionary socialist party in the Kerala legislature also walked out.

They walked out in protest against the policy of the Chief Minister. It was three days earlier that Mr. Wellington, one of the ministers in the Kerala Cabinet, announced in a public meeting that a stage has been reached when the people should organise themselves in order to protest themselves when there are attacks against them and the police do not come to their help.

I made the charge and I repeat it now that in Kerala if there is an attack by the Marxist against farmers, labourers and others, the police will not raise their little finger, even if a complaint is made. On 19th September, about 100 workers in Trichur led by a Marxist Communist entered the State Bank of India in Trichur and was about to enter into the cash box room. The manager of the State Bank requested the police to come to his help to protect the State Bank of India.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he has stated certain facts which are not correct, you can contradict them. From the procedural point of view, there is nothing.

SHRI S. M. BANERJEE : Under rule 376, I am raising the point of order. The business before the House, according to the paper, is...

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you say the Minister is irrelevant, I cannot agree. On a point of personal explanation, he is intervening and he has a right. (*Interruption*).

श्री सत्य नारायण सिंह (वाराणसी) : हम को ये माम्रो के चेले बताते हैं। ये किस के चेले हैं ? क्या ग्रमरीका के चेले नहीं हैं, च्यांग काई शेक के चेले नहीं हैं ? जो मन में ग्राता है कह देते हैं। मजाक समझ रखा है। जो चाहो बोल दो। बड़े ग्राए देश भक्त। क्या ग्राप ही देश भक्त रह गए हैं ? हम नहीं हैं......

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nambiar, I will have to take action against that member. I will not tolerate it.

SHRI S. M. BANERJEE : He wants to say something on a point of personal explanation. May I invite your attention to the rule relating to personal explanation ? If there are any charges made against him, he can say that they are baseless. It should be confined to that. But he has brought in the conduct of the Chief Minister and certain other issues which purely concern the Home Ministry. He has said that somebody entered the State Bank etc. He should confine himself absolutely to the charges that have been made and say whether they are correct or not.

18.03 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No further explanation is necessary. Please resume your seat. The question is....

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : The point is....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat. I do not want any assistance to dispose of the point of order. I am not going to listen to it... .... *Interruptions*). Nothing will go on record. (*Interruptions*).*

श्री ग्रब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : डिप्टी स्पीकर साहब, ग्राप बहुत बड़े हैं ग्रौर ग्राप के ग्रधिकार भी बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन है कि पांच ग्रादमी निकल गये ग्रौर सात ग्रादमी वाक ग्राउट कर गये, वगैरह ?

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگانوہ) : ڈپٹی سپیکر صاحب ، آپ بہت بڑے ہیں اور آپ کے ادھیکار بھی بہت بڑے ہیں ، لیکن کیا یہ پرسنل ایکس پلینیشن ہے کہ پانچ آدمی نکل گئے اور سات آدمی واک آؤٹ کر گئے ، وغیرہ ؟]

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already disposed of the point of order. Certain allegations were levelled against the Law Minister for certain statements supposed or alleged to have been made by the Law Minister. If certain allegations,—I do not know whether they are true or not—are levelled against him by one side, it is perfectly within his right to give a personal explanation with all the evidence at his disposal.

SHRI NAMBIAR : My point of order is different. He is a member of the Union Cabinet. So, he is not speaking only as a member of the House. So far as he is concerned, he can say what he said or did. But, if he goes beyond that and makes allegations against a State Government, it becomes within the purview of Centre-State relationship. Therefore, I would request the Chair that he should not be allowed to go beyond the limits. Since his previous utterances are quoted, let him by all means refer to them. But if he indulges in making baseless charges against a State Government, it should be taken as a statement by the Union Government against a State Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your question is whether he spoke in his capacity as Law Minister or as a party member. I am not concerned with it. When you attack him here, you attack him both in his capacity as Shri Govinda Menon and also his capacity as Law Minister. Keeping in view that dual capacity, he is perfectly within his right to give an explanation.

SHRI S. M. BANERJEE : What is his capacity now ?

SHRI GOVINDA MENON : I will conclude soon because the matter falls

*Not recorded.

[Shri Govinda Menon]

within a small compass. As I said, I am intervencing in the debate by way of personal explanation.

The statement which I made was that the Marxists committed aggression against others.

SHRI NAMBIAR : Aggression ?

SHRI GOVINDA MENON : Yes. When Marxists attacked others, attacked their property, attacked their person, what is found in Kerala today is...(*Interruptions*). Please listen ; this is my allegation. When that happened, police did not come to help the people.

That is my first statement. By way of an illustration I wanted to refer to what happened on the 19th September. When the State Bank of India was attacked, the manager of the State Bank requested the District Collector and the District Superintendent of Police to go to his help and they said that they would not go. They did not go and on that day the State Bank of India had to be closed for want of police help from 10 to 11 A.M. This I wanted to say to illustrate my point.

When the Marxists and those led by them do something to break the law the police do not raise their little finger against it. In a situation like that—I pose the question—what shall we do ?

SHRI VASUDEVAN NAIR : What about your lathis and your goondas ? I saw that with my eyes—Congressmen doing that in Kottayam.

SHRI GOVINDA MENON : In a situation like that I said that this is the right, the duty, what is sanctioned by law, for people to protect themselves..... (*Interruption*). This is all I said. I did not say that the people should take the law into their own hands to topple the Kerala Government.....(*Interruption*)- If Congressmen, the Right Communists or the RSP or anybody else commit acts of violence then also the police must come and take action against them and protect the victims. If somebody attacks a police station, then also the police must go there. Shri Vasudevan Nair grew eloquent about certain agitations in Kerala today on account of certain beneficial legislative measures which are being taken. I do not take it, Sir, that it is on account of these beneficial measures that two police stations were attacked in Kerala.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : On a point of order, Sir.

SHRI VASUDEVAN NAIR : What is your attitude to the University Act ? Have you the courage to say about that ?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : The Law Minister was saying that when law and order breaks down in a State what happens. There is the Indian Penal Code made by Parliament. Under article 256 this Government has got every right to give directions.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why was a directive not issued by the Central Government, when there was a breakdown of law and order ? This is a charge against you.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : When there is a breach of the law made by Parliament, the Central Government has got a right to issue directions under article 256 Everyone knows that. Our Law Minister knows it very well that if there is any breach of law in a particular State, whether it is in Kerala or in any other part of India, his duty is to bring it to the notice of the Home Minister and to see that a direction is issued under article 256 and not to incite the people to take to arms or to sticks. That is an act of the goondas and not of the Law Minister. He ceases to be a Law Minister the moment he says that people have got a right to take to sticks.

SHRI S. M. BANERJEE ; He should be sacked.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : He should be dismissed.

SHRI INDRAJIT GUPTA : The Government should be sacked for not locking him up.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : He ceases to be the Law Minister when he advocates that people should take to arms or sticks.

SHRI GOVINDA MENON : I have not said anything like that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : While giving an opportunity on a point of personal explanation..... (*Interruption*).

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : If you demand, we will justify what he has done . (*Interruption*)

SHRI VASUDEVAN NAIR : Did he refute the statement which I alleged he had made ?

SHRI GOVINDA MENON : Yes.

SHRI VASUDEVAN NAIR : No. He has an explanation for it but he stands by it..... (*Interruption*). Let the people of India see that the Law Minister..... (*Interruption*)

SHRI GOVINDA MENON : They should defend themselves and not wait for a directive from the Centre.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : He is not the type of Law Minister we should have.

SHRI VASUDEVAN NAIR : He says that the people can take law into their own hands... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a point of disorder now. I will have to adjourn the House. Order, order. Let me dispose of the point of order.

SHRI RANDHIR SINGH : It is 6.10 P.M. now. They do not want you to proceed. Better adjourn the House if they do not want to listen. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. The point that you have raised has some relevance. To that extent, I will explain. I have never pronounced any verdict regarding the doctrine of collective defence. Whether the doctrine of collective defence was preached in the capacity of the Law Minister or a Member of a Party, I have not said anything on that. You cannot raise any objection. I have not said anything of that sort.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : He has made the speech as by Mr. Govinda Menon, not as the Law Minister. (*Interruptions*)

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । अभी आप ने कहा कलेक्टिव डिफेंस...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड) : हमें भी कुछ कहना है इस हाउस में । यह प्वाइंट आफ आर्डर, प्वाइंट आफ आर्डर, कब तक चलेगा ? अगले वक्ताओं को बुलाइए । सारा समय हाउस का जा रहा है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जो ला मिनिस्टर ने कहा, अगर ला मिनिस्टर समझते थे कि ब्रेक हो गया है बिलकुल ला ऐंड आर्डर का तो इन का यह फर्ज था कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते कि प्रोटेक्शन दे और लोगों को प्रोटेक्शन देने में यह सरकार कमजोर रही है, इस ने कुछ काम नहीं किया, यह हमारा चार्ज है । लेकिन ला मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें वह नहीं कहना चाहिए था । एक व्यक्ति की हैसियत से कह सकते थे । यह हर एक आदमी को कहने का हक है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri P. Gopalan.

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is in the background of the growing economic crisis and the consquent political crisis in our country that we are discussing this problem of Centre-State relations. I think, without going into the economic and political aspects of the problem underlying this relationship, we will not be able to understand the real issue as such. Everybody knows that during the last 21 years, a capitalist economy is being built up in our country and the Congress Party which has been in power has been developing this type of capitalism and that has developed into monopoly capitalism. It is the deve-

[Shri P. Gopalan]

lopment of monopoly capitalism that has resulted in the concentration of wealth in the hands of a few privileged people. It is this concentration of wealth in the hands of a few privileged people that has, recently, reflected in the political field of our country. These are the economic and political reasons underlying the Centre-State relations. The State Governments are asking for more powers while the Central Government is clamouring for more and more powers. The State Governments are asking for maximum autonomy and more powers. The Central Government is, gradually, taking away the powers of the State Governments. For example, during the recent strike of the Central Government employees, an Ordinance was promulgated.

Certain directives were issued to all the State Governments to be carried out, and the Kerala Government took a different position. Under this Ordinance, our Home Minister, Shri Chavan, gave certain instructions to the State Government exercising his discretionary power regarding arrest of the political leaders who instigated the strike. He has blamed the State Minister for non-implementation of this order. But the Chief Minister has replied that, if the Central Home Minister has the power to exercise his discretion, the State Chief Minister has also his own discretion not to arrest any of the leaders who instigated the strike.

Another factor is also there. The Kerala State Government has come into power on a different political platform. The political programme of the Kerala State Government is different from that of the Congress Central Government. While the Central Government is suppressing the labour movements in our country and is taking an open stand against the working class of our country, the Kerala Government is standing on the side of the working class of our country. It is upon these different political programmes that these two Governments are constituted.

Our State Government has taken a very clear position with regard to labour disputes. The Central Government employees issue being essentially a labour issue, our Government took a position as to how it should be dealt with. The Central Government usually supresses those movements, labour movements. But the State Government took a different position. How can the Central Ministers hope that the State Government will automatically follow the anti-working class policy of the Congress Government while the State Government has come into power on a different political programme and political platform ? This is what we cannot understand.

I now come to the question of the attitude of the Central Government towards our State, and especially of our Law Minister, Shri P. Govinda Menon, who is the only Congress member from Kerala in this House and for which virtue he has been pitch-forked to that important position of Cabinet Minister. Everybody knows him .. (*Interruptions*) Mr. Govinda Menon is well known in Kerala, even young children know him, not because of his magnanimous activities here as a Cabinet Minister, not because of his outstanding personality, but because everybody remembers an incident. This Mr, Govinda Menon has branded the EMS Government as a Government of dacoits. In one of his speeches, he has said this.....

SHRI GOVINDA MENON : Quote it.

SHRI P. GOPALAN : Yes ; I am quoting. I am quoting from *Kerala Kaumadi* which always supports Congress.....

SHRI GOVINDA MENON : That is a wrong report.

SHRI P. GOPALAN : I am quoting :

> "The Union Law Minister, Shri P. Govinda Menon, today described the EMS administration in Kerala as a Governmoet of dacoits....."

SHRI GOVINDA MENON : That is a wrong report.

SHRI P. GOPALAN : You will deny everything. That is what you usually do. Why did you not deny this when it appeared in the paper ? Where had you been at that time ? (*Interruption*)

SHRI GOVINDA MENON : I have not seen that. That is a wrong report.

SHRI P. GOPALAN : Then, it is said :

"He exhorted the people to be ready to resist this Government and to mobilise in sufficient strength to make the resistance successful."

This was his open call.....

SHRI GOVINDA MENON : This is wrong.

SHRI P. GOPALAN : This is not wrong. I know, you will deny it..(*Interruptions*) Mr. Govinda Menon has characterised and blamed the EMS Government as a Government of dacoits.

SHRI GOVINDA MENON : I have not done that.

SHRI P. GOPALAN : He is well remembered in Kerala because of this incident ; he is the popular hero of a drama enacted in Kerala some years back, notoriously known as the '5½-lakh sugar scandal' ; he is popularly known more as '5½-lakh' than as 'Panampalli' Govinda Menon.....

SHRI NAMBIAR : Children even sing songs.

SHRI P. GOPALAN ; This is the type of man that he is. We will not be surprised of this if Mr. Panampalli Govinda Menon had said this in his personal capacity, but what we are astonished to see is that a Union Minister, Mr. P. Govinda Menon, is indulging in such a propaganda. Mr. Govinda Menon has tried to prove that the Marxist Communists are attacking the other sections.....(*Interruptions*)

SHRI GOVINDA MENON : That I have said.....

SHRI P. GOPALAN : Sir, I would like to ask him : How many Marxist communists were butchered by your Congress goondas ? In my district how many communist comrades have butchered by your congress goondas ? (*Interruption*)

In 1959 what happened ? I was beaten up during that time. This Congress started the liberation struggle.....(*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must conclude now.

SHRI P. GOPALAN : Sir, so many buses were destroyed ; so much loss had taken place, due to the struggle waged by these Congress people. Yet, it is these people now who are talking from their house-tops about the sanctity of the constitution. These people have butchered democracy,—a cold-blooded butchery—which they did in July, 1959. Now they say Marxists and communists have no faith in democracy.

SHRI GOVINDA MENON : They say so.....

SHRI P. GOPALAN : They say, Sir, that we do not respect the constitution and all that. May I ask him : Does he respect the Constitution ? If he respects the constitution, he has the moral obligation and the political obligation to follow only constitutional methods, but what they followed were unconstitutional and undemocratic methods. If there is something wrong, they ought to have followed democratic and constitutional methods but not these clandestine methods. These methods will not do. This man, Shri Govinda Menon, is not worthy to sit there. He must resign. I have the least respect for him. He must resign. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to call.....

SHRI NAMBIAR : There is a corruption charge of Rs. 5½ lakhs against him. Is he worthy of sitting there, Sir ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to call Shri Dwivedy, Shri Joshi, Shri Prakash Vir Shastri and two others from this side. The Home Minister has to reply. It will take a long time. May I know the desire of the House ? Is it the desire of the House that we may adjourn ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI (Kendrapara) : We will have it tomorrow.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : One submission. Sir, before we adjourn.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : It will take another 1½ hours now.....

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI : Will you take this up tomorrow or on some other day ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : How can I predict just now ? It is for you to meet hon. Speaker and discuss so that time may be fixed. The House stands adjourned to meet at Eleven of the Clock tomorrow.

18.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 4, 1968 / Agrahayana 13, 1890 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj, Delhi-6.